

नदियों का अंतर्याजन

नीरज कुमार भटनागर
रा.ज.सं.,रूड़की

लगभग 120 करोड़ की आबादी वाला भारतवर्ष वर्तमान समय में जल की अत्यन्त कमी का सामना कर रहा है। अगर समय रहते इस समस्या का निदान नहीं किया गया तो भविष्य अत्यन्त भयावह होगा। हमारे देश का एक बड़ा भाग अपनी जल आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दक्षिणी-पश्चिमी मानसून पर निर्भर रहता है। मानसून की अनिश्चितताओं के कारण यह आवश्यक हो गया है कि जल जैसे बहुमूल्य संसाधन का अत्यन्त दक्षता व चतुराई के साथ प्रबंधन किया जाए।

इस दिशा में एक प्रयत्न यह भी है कि भारतवर्ष की मुख्य नदियों को परस्पर जोड़ दिया जाए, गंगा नदी बेसिन को नहर द्वारा कावेरी नदी से जोड़ने की एक योजना के.एल.राव द्वारा प्रस्तावित की गयी थी। इसके बाद ब्रिटिश कप्तान दस्तूर ने "गारलैण्ड कैनल" नामक प्रस्ताव को 1950 में देश के सामने रखा। नदियों को आपस में जोड़ने की योजना बहुत ही आकर्षक और लाभकारी प्रतीत होती है इसका मूल आधार यह है कि भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में जल मात्रा की उपलब्धता में बहुत विभिन्नता तथा अनिश्चितता है। जहाँ एक तरफ ग्लेशियरों द्वारा जल प्रदत्त हिमालयी नदियाँ भारतीय मैदानी भागों में पूरे वर्ष भर प्रवाहित होती रहती हैं वहीं दूसरी ओर प्रायद्वीपीय नदी तंत्र पूरी तरह से सीजनल (seasonal) है और अपने वार्षिक प्रवाह के 80% के लिये दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर निर्भर रहता है। जहाँ हिमालयी नदियाँ बाढ़ प्रभावित रहती हैं ठीक उसी समय प्रायद्वीपीय नदियों के बेसिन सूखा ग्रस्त रहते हैं। अतः उक्त समस्या व स्थिति को देखते हुए नदियों के अतिरिक्त जल की मात्रा को कम जल वाले क्षेत्रों में स्थानान्तरित करने के विचार ने जन्म लिया।

इस योजना के विषय में कहा गया कि नदियों को परस्पर जोड़ने से जल संसाधनों का न केवल महत्तम उपयोग हो सकेगा बल्कि इसके बहुआयामी सामाजिक-आर्थिक (socio-economic) व पर्यावरणीय लाभ भी होंगे। नहरों के तंत्र को बनाये जाने के कारण काफी बड़े क्षेत्र सिंचाई की सुविधा पा सकेंगे जिसके कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी व खाद्यान्न सुरक्षा मिल सकेगी इसके साथ-2 सस्ता व पर्यावरण की दृष्टि से अच्छा परिवहन साधन उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त जल ऊर्जा उत्पादन होगा जिसके कारण ऊर्जा सुरक्षा भी प्राप्त होगी। कमांड एरिया में भूजल स्तर के ऊँचा होने पर वनों व वानस्पतिकी में वृद्धि होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस परियोजना के कारण राष्ट्र एकता की भावना को बल मिलेगा जो अपने आप में आज के समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। उपरोक्त रेखांकित चित्र बहुत लुभावना है परन्तु अगर इसका ध्यान से विश्लेषण किया जाए तो एक भयानक सच्चाई से सामना होता है। इतनी बड़ी परियोजना के लिये विस्तृत नियोजन, अध्ययन व विश्लेषण की आवश्यकता है। इसकी तुलना में छोटी परियोजनाओं जैसे कि भाखड़ा-नांगल और नर्मदा पर सरदार सरोवर व अन्य ने पूरा होने में कई दशक का समय लिया तब अन्तर्याजन में कितना अधिक समय लगेगा ?

"अतिरिक्त जल" की अवधारणा जो कि इस परियोजना का मूल आधार है अपने आप में काफी भ्रमित करने वाली है क्योंकि हिमालयी नदियों के जल संग्रहण क्षेत्र सूखे के समय में सूखाग्रस्त रहते हैं। जल संग्रहण हेतु जलाशय बनाने के लिये बहुत पैसा व्यय होगा साथ-2 ही इन स्थलों का निर्धारण व स्थानीय पर्यावरण पर उनके प्रभाव अनुत्तरित प्रश्न है। कुछ अनुमानों के अनुसार इस परियोजना पर 250 बिलियन यू.एस.डॉलर से भी ज्यादा खर्च आ सकता है इतनी बड़ी धनराशि कहाँ से आयेगी ? आर्थिक अस्थिरता के समय में सरकार इतने अधिक धन का प्रबन्धन

कैसे करेगी यह एक गम्भीर प्रश्न है। इस संदर्भ में निजी संस्थाओं द्वारा निवेश भी नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसके कारण जल के व्यावसायीकरण का खतरा उत्पन्न हो सकता है। इस परियोजना में धन निवेश हेतु सरकार वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक से ऋण ले सकती है पर यह सदैव सशर्त होता है। अतः किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिये एक सम्पूर्ण कॉस्ट-बेनिफिट विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।

एक बहुत ही प्रभावी आंशका व्यक्ति की जा रही है कि क्या ये परियोजना पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित है। नहरों को बनाने, सिंचाई तंत्र, बाँध और जलाशयों के निर्माण के दौरान विशाल वन क्षेत्रों का कटान, जमीन का पानी में डूबना और पहाड़ों का कटाव आदि कार्यों के कारण पर्यावरण निश्चित रूप से प्रभावित होगा। इसके अतिरिक्त जल को समुद्र में जाने से रोकने के भी निश्चित दुष्प्रभाव होंगे उदाहरणार्थ समुद्री जीव जन्तुओं का जीवन प्रभावित होगा तथा डाउन स्ट्रीम डेल्टा क्षेत्रों के पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ेगा जिसके कारण स्थानीय आर्थिक स्थितियों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। अन्तर्गोजना परियोजना एक बहुत बड़ा कार्य है इसके कारण लाखों-करोड़ों लोगों को विस्थापित करना व पुनर्वास करना पड़ेगा जो कि एक भयानक समस्या है। अतः सरकार का यह कर्तव्य है कि इस परियोजना को प्रारम्भ करने से पहले यह निश्चित कर ले कि इतनी बड़ी जनसंख्या को पुनःस्थापित करने व मुआवजा देने हेतु पूरे साधन हैं या नहीं। इसके पूर्व की कुछ परियोजनाओं जैसे कि सरदार सरोवर परियोजना या टिहरी डैम परियोजना के अनुभव इस विषय में ज्यादा अच्छे नहीं हैं। एक अन्य बिन्दु पर विचार करें तो पहाड़ों व कठिन स्थलों पर जल को ऊपर उठाने (lifting) हेतु अत्यधिक विद्युत ऊर्जा की जरूरत होगी जिसकी उपलब्धता पहले से ही ऊर्जा की कमी झेल रहे राष्ट्र को सुनिश्चित करना एक दुष्कर कार्य होगा।

स्वतंत्र भारतवर्ष में पहले से ही जल के बंटवारे को लेकर बहुत मतभेद हैं उदाहरणार्थ कर्नाटक व तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद। यद्यपि नदी जल ट्रिब्यूनल व अन्तर्राज्यीय काउन्सिल जैसी कानूनी व संस्थागत तंत्र ऐसे विवादों को सुलझाने के लिये स्थापित हैं परन्तु इस परियोजना के प्रारम्भ होते ही जो विवाद बेसिनों के मध्य उत्पन्न होंगे उनको सुलझाने हेतु कोई तंत्र नहीं है। इंजीनियरी अन्तर्राज्यीय मतभेदों के अतिरिक्त इस परियोजना के कारण पड़ोसी देशों से भी राजनयिक समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पर आने वाले समय में नेपाल की हिमालयी नदियों का दोहन करने की अपनी योजनाएँ हैं जो कि भारतवर्ष की योजनाओं से सहमत नहीं हो सकती। इसी प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी का पानी मोड़ने पर बंगलादेश को आपत्ति हो सकती है।

भारतवर्ष की जल सम्बन्धी समस्याओं का कोई एक हल नहीं हो सकता हमें एक बहु - विमीय (multi dimensional) एप्रोच पर काम करना पड़ेगा। तुरन्त काम आने वाली योजना यह हो सकती है कि जहाँ भी वर्षा होती है वह जल वहीं संग्रह किया जाए ताकि जल की कमी वाले समय में इसका उपयोग किया जा सके। दूसरे शब्दों में स्थानीय व गांव के स्तर पर वाटर शेडों को स्थापित कर वर्षा जल का संचयन किया जाए। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों व स्थापित पुराने ज्ञान की मिश्रित तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए। स्थानीय स्तरों पर छोटे-2 अंतर्गोजना बनाये जा सकते हैं जिससे कि न्यूनतम पुनःस्थापन व पर्यावरणीय नुकसान की कीमत पर ज्यादा से ज्यादा लाभ लिए जा सकें।